

जनपद फर्रुखाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास स्तर की भौगोलिक विवेचना

प्राप्ति: 13.02.2021

स्वीकृत: 05.03.2021

डॉ० नरेश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग

मेरठ कालिज, मेरठ

[Email: nareshkakran@gmail.com](mailto:nareshkakran@gmail.com)

महेन्द्र कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग

राजकीय महाविद्यालय, कासगंज

kumarmahendra070@gmail.com

सारांश

ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य जनपद के निवासियों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए उत्पादन, उत्पादकता तथा आय के स्तर में अभिवृद्धि करना होता है। विकास का क्रम निचले स्तर से अर्थात् प्रथम गाँव से विकासखण्ड और जिले से राज्य स्तर पर होना अति लाभकारी होता है। ग्रामीणों में कृषि के अतिरिक्त उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों में भी रोजगार के अवसरों में विस्तारीकरण किया जाना आवश्यक है; जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को जीविकोपार्जन हेतु लाभकारी रोजगार उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी समाप्त करने, ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करना तथा ग्रामीण निर्धनों की प्राथमिक आवश्यकताओं को रेखांकित करने और उनकी पूर्ति हेतु व्यापक रूप में सर्वेक्षण अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारतीय बैंकों को अधिक ध्यान देना होगा।

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य जनपद के निवासियों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए उत्पादन, उत्पादकता तथा आय के स्तर में अभिवृद्धि करना होता है। विकास का क्रम निचले स्तर से अर्थात् प्रथम गाँव से विकासखण्ड और जिले से राज्य स्तर पर होना अति लाभकारी होता है। ग्रामीणों में कृषि के अतिरिक्त उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों में भी रोजगार के अवसरों में विस्तारीकरण किया जाना आवश्यक है; जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को जीविकोपार्जन हेतु लाभकारी रोजगार उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी समाप्त करने, ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करना तथा ग्रामीण निर्धनों की प्राथमिक आवश्यकताओं को रेखांकित करने और उनकी पूर्ति हेतु व्यापक रूप में सर्वेक्षण अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारतीय बैंकों को अधिक ध्यान देना होगा।

जनपद की भौगोलिक अवस्थिति

उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर मण्डल के अन्तर्गत स्थित फर्रुखाबाद जनपद कृषि प्रधान जनपद है। इसका अक्षोशीय विस्तार $27^{\circ} 9' 02''$ उत्तर से $27^{\circ} 43' 31''$ उत्तर तक तथा देशान्तर्रीय विस्तार $79^{\circ} 4'$ पूर्व से $79^{\circ} 44' 21''$ पूर्व तक है। गंगा नदी इसकी उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर दिशा में शाहजहाँपुर एवं बदायूँ जनपद, दक्षिण में कन्नौज जनपद, पूर्व में हरदोई जनपद तथा पश्चिम में एटा एवं मैनपुरी जनपद स्थित हैं।

अध्ययन क्षेत्र लगभग वर्गाकार आकृति में है। उत्तर-पूर्व का कम्पिल वाला क्षेत्र नुकीला तथा उभरा हुआ है। शाहजहाँपुर जनपद की सीमा उत्तर दिशा में थोड़ी सी धसी हुई है। जनपद को पतंगाकार कहा जा सकता है। जनपद की उत्तर से दक्षिण लम्बाई 56 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 45 कि०मी० है। उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व अधिकतम लम्बाई 62.50 कि०मी० है। यही लम्बाई इसे पतंग का आकार प्रदान करती है।

जनपद में अधिवासित ग्राम 881 तथा अनाधिवासित 129 ग्राम हैं। सर्वाधिक अधिवासित ग्राम 150 कायमगंज विकासखण्ड में है। तहसील सदर फर्रुखाबाद में 40 ग्राम पंचायतें तथा 228 ग्राम सभायें हैं। कमालगंज विकासखण्ड में सर्वाधिक 17 ग्राम पंचायतें 96 ग्राम सभायें हैं तथा 162 अधिवासित ग्राम हैं। 9 न्याय पंचायतें, 49 ग्राम सभायें, 81 अधिवासित ग्राम तथा 15 अनाधिवासित ग्राम नवाबगंज विकासखण्ड में हैं। तहसील अमृतपुर में 13 न्याय पंचायतें तथा 72 ग्राम सभायें हैं। राजेपुर विकासखण्ड में 136 अधिवासित ग्राम हैं। जनपद फर्रुखाबाद में कुल ग्रामों की संख्या 1010 है जिसमें 881 अधिवासित ग्राम हैं तथा 129 अनाधिवासित ग्राम हैं।

सारणी क्रमांक 1

जनपद फर्रुखाबाद : ग्रामीण प्रतिरूप (वर्ष 2019)

क्र० सं०	विकासखण्ड/ तहसील का नाम	न्याय पंचायत	ग्राम संख्या	अधिवासित ग्राम	अनाधि वासित ग्राम	कुल योग
1.	कायमगंज	12	76	150	27	177
2.	नवाबगंज	09	57	88	2	90
3.	शमसाबाद	13	78	143	31	174
	तहसील कायमगंज	34	211	381	60	441
4.	बदरपुर	09	49	81	15	96
5.	कमालगंज	17	96	162	23	185
6.	मोहम्मदाबाद	14	83	121	01	122
	तहसील सदर फर्रुखाबाद	40	228	364	39	403
7.	राजेपुर	13	72	136	30	166
	तहसील अमृतपुर	13	72	136	30	166
	जनपद फर्रुखाबाद	87	511	881	129	1010

स्रोत : राजस्व रिकार्ड, जनपद फर्रुखाबाद

जनपदीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहाँ की लगभग 77.92 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इस प्रकार प्रत्येक चार भारतीयों में से 3 गाँवों में निवास

करते हैं।¹ देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 34 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से ही प्राप्त होता है। अतः यह निर्विवाद है कि भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि, सिंचाई, पशुपालन, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, सहकारिता एवं ग्रामीण उद्योग आदि पर विशेष ध्यान दिया गया तथा अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। इन विकास कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0) है। इस कार्यक्रम के साथ-साथ ग्रामीण निर्धनता निवारण हेतु ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना आदि कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है।

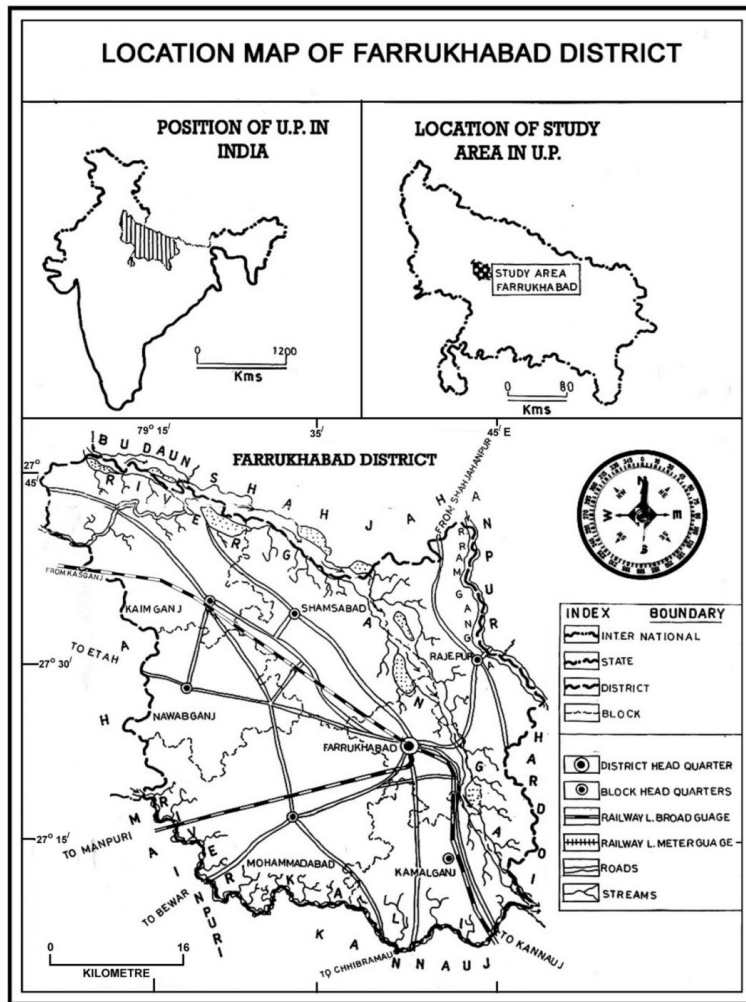


FIG. 1

विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन से इस बात की पुष्टि तो हुयी है कि इनका लाभ ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों तक पहुँच रहा है, लक्ष्य प्राप्ति में भी सफलता मिली है, परन्तु आय बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियाँ लगभग आधी ही बैठती हैं। लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति न हो पाने का प्रमुख कारण इन कार्यक्रमों के संचालन में समय-समय पर अनेक प्रकार के अवरोधों का उत्पन्न होना है।

अध्ययन का उद्देश्य

सर्वप्रथम ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को मिलाकर एक समाकलित कार्यक्रम बनाया गया जिसमें निर्धनता उन्मूलन, रोजगार के अवसरों का सृजन, प्रशिक्षण तथा वित्तीय अनुदान और सहायता आदि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र का चयन करके इस शोधलेख में समाकलित ग्रामीण विकास के माध्यम से निम्न उद्देश्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है –

1. ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य कृषि संसाधनों का विश्लेषण करके विकास एवं नियोजन प्रस्तुत करना है।
2. वर्तमान कृषि स्वरूप के संदर्भ में ग्रामीण जनसंख्या का सामाजिक-आर्थिक प्रारूप के अन्तर्सम्बन्ध की व्याख्या प्रस्तुत करना है।
3. समग्र ग्रामीण विकास हेतु आधारभूत अवसंरचना का नियोजन एवं विकास करना है।

साहित्य का पुनरावलोकन

सिंह² (2010) ने समाकलित ग्रामीण विकास उपागम के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति हेतु भू-वैन्यासिक नियोजन के द्वारा ग्रामीण निवास्य प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को आवश्यक मानकर इस संकल्पना को एक नया आयाम प्रदान किया है। श्रीवास्तव³ (1992) के अनुसार समाकलित ग्रामीण विकास अपेक्षाकृत अधिक संतुलित, विस्तृत एवं सर्वांगीण विकास का एक उपागम है जिसके द्वारा भौगोलिक, संस्थागत, आर्थिक एवं सामाजिक समन्वयन स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश निर्धन जनसंख्या के जीवन-स्तर में सुधार एवं उनके विकास-माध्यम को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। भार्गव⁴ (2006) के अनुसार –समाकलित ग्रामीण विकास के सर्वांगीण उपागम की उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान विपन्नता एवं द्वैधात्मक अर्थतन्त्र के विभिन्न कारणों यथा उच्च जन्मदर, बेरोजगारी, कृषि निवेशों एवं प्राविधिकी की अनुपलब्धि, सक्षम ग्रामीण संस्थाओं प्राधिकृत जनसहयोग के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के अभाव जैसी समस्याओं के निराकरण से सम्बन्धित है।

परिकल्पनायें

प्राचीन समय में मानवीय सामर्थ्य को जनसंख्या के संख्यात्मक रूप में स्वीकार किया जाता था तब परम्परागत कृषिगत समाज मानवीय श्रम की अधिकांश कार्यों में आवश्यकता होती थी। अतः संख्यात्मक दृष्टि से अधिक जनसंख्या का अभिप्राय अधिक उत्पादकता और समृद्धि से लगाया जाता था किन्तु वर्तमान में इन सन्दर्भ में विज्ञान तकनीकी और औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं जिससे मानवीय संख्यात्मक स्थिति के ऊपर निर्भरता कम

हुई है तथा तकनीकी के अत्यधिक उन्नति साधनों के संचालित करने के लिए बौद्धिक क्षमता एवं सामर्थ्य की आवश्यकता है जिससे उत्पादन, बहुविधि तथा बहुगुणित हो सके। इस प्रकार जनसंख्या का गुणात्मक विकास संख्यात्मक वृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण होता गया, तथा किसी भी क्षेत्र की आर्थिक दक्षता व उत्पादकता, विकास पर सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की गुणवत्ता की छाप होती है। क्या कृषि विकास से ही ग्रामीण विकास सम्भव है। इस परिकल्पना को सिद्ध करना है।

विधितंत्र

ग्रामीण समस्याओं के निराकरण हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समकों का उपयोग किया गया है। प्राप्त समकों का सांख्यिकीय विधियों से आगणन करके मानचित्रण कार्य किया गया है। इस हेतु गतिशील मानचित्रात्मक एवं रेखाचित्र विधियों का उपयोग किया गया है। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियों का कृषि के परिप्रेक्ष्य में रैखिक विधि द्वारा मानक विचलन के आधार पर क्षेत्रीय प्रतिरूपों को स्पष्ट किया गया है।

कृषि विकास स्तर

कृषि विकास स्तर एवं कृषि दक्षता समान अर्थप्रदायक है, कृषि विकास स्तर में मानव द्वारा फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त प्रयास एवं परिणाम का अभाव होता है। जबकि कृषि दक्षता में कृषि उत्पादन क्षमता का अभिज्ञान होता है। अतः कृषि विकास स्तर क्षेत्रीय वितरण में विशमताओं के आधार पर कृषि प्रतिरूप के नियोजन को निर्धारित करता है, कृषि दक्षता भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन कृषि विकास स्तर में मनुष्य के आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अतः जनसंख्या एवं कृषि संसाधनों में सन्तुलन एवं नियोजन हेतु कृषि विकास स्तर का अध्ययन अति आवश्यक होता है। जनपद फर्रुखाबाद में सूचकांकों को आधार मानते हुए कृषि विकास स्तर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित विधि अपनाई गई है –

प्रयुक्त सूचकांक

1. शुद्ध बोया गया क्षेत्र/कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
2. शुद्ध बोया गया क्षेत्र/कृषक श्रमिकों की संख्या
3. सिंचित क्षेत्र/असिंचित क्षेत्र
4. एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र/शुद्ध बोया गया क्षेत्र
5. मुद्रा दायिनी फसलों का क्षेत्र/खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र
6. कृषि श्रमिकों की संख्या/कृषकों की संख्या
7. लोहे के हलों की संख्या/लकड़ी के हलों की संख्या
8. ट्रैक्टरों की संख्या/शुद्ध बोया गया क्षेत्र
9. प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का प्रयोग (मीट्रिक टन में)
10. प्रति वयस्क उपलब्ध खाद्यान्न की वार्षिक मात्रा (कुन्तल में)

कृषि विकास स्तर की गणना हेतु उपर्युक्त सभी सूचकांकों का वास्तविक मान तथा उनका औसत माध्य ज्ञात किया जाए। तत्पश्चात् वास्तविक मानों में समानता लाने हेतु वास्तविक मानों का औसत माध्य से भाग देकर प्राप्त हुए मान का योग करके प्राप्त सूचकांक के आधार पर कृषि विकास स्तर ज्ञात किया गया है।

कृषि विकास स्तर की कोटियाँ

कृषि विकास स्तर सूचकांक के आधार इसको उच्चतम, उच्च, मध्य, निम्न एवं निम्नतम पांच कोटि वर्गों में विभाजित करके श्रेणीबद्ध किया गया है। फर्रुखाबाद जनपद में कृषि विकास स्तर अधिकांश क्षेत्रों में माध्यम एवं मध्यम से भी नीचे निम्न एवं निम्नवत् है। अतः कृषि संसाधनों एवं जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए नियोजनों हेतु निम्न कृषि विकास स्तर के क्षेत्रों में कृषि की नवीन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कृषि विकास स्तर में वृद्धि की जा सकती है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए 'कुलकर्णी' आदि ने भी इसकी संस्तुति प्रदान की है। कृषि फसलों के उत्पादन एवं कृषि भू-दृश्यों का विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण करने के उपरान्त स्पष्ट होता है कि विभिन्न कृषित पदार्थों का सम्बन्ध वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकता से बहुत कम है।⁶ जिससे मनुष्य को उपयुक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप मनुष्य विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित है अतः मनुष्य को संतुलित भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है।

उक्त सूचकांकों के आधार पर विकास स्तर मापन किया गया तो निम्नलिखित परिदृश्य उभरकर सामने आये कि सम्पूर्ण जनपद में उच्च कृषि विकास स्तर 17.40 कमालगंज विकासखण्ड में पाया गया जो कि सर्वाधिक है। शमसाबाद भी उच्च विकास स्तर वाला क्षेत्र है। मध्यम विकास स्तर जनपद के तीन विकासखण्डों कायमगंज, राजेपुर तथा बड़पुर में पाया गया है। जनपद में निम्न विकासस्तर नबावगंज और मोहम्मदबाद विकासखण्डों में है।

सारणी क्रमांक 2

जनपद फर्रुखाबाद : कृषि विकास स्तर (2018-19)

क्र०सं०	विकासखण्ड	विकास सूचकांक	विकास कोटि
1.	कायमगंज	14.17	मध्यम
2.	नबावगंज	08.97	निम्न
3.	शमसाबाद	16.09	उच्च
4.	राजेपुर	11.08	मध्यम
5.	बड़पुर	14.02	मध्यम
6.	मोहम्मदबाद	09.65	निम्न
7.	कमालगंज	17.40	उच्च

निम्न व मध्यम कृषि विकास स्तर वाले क्षेत्रों में कृषि की नवीन वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या भी विकास स्तर को प्रभावित करती है अतः जनसंख्या वृद्धि को नियोजित करके वांछित विकास

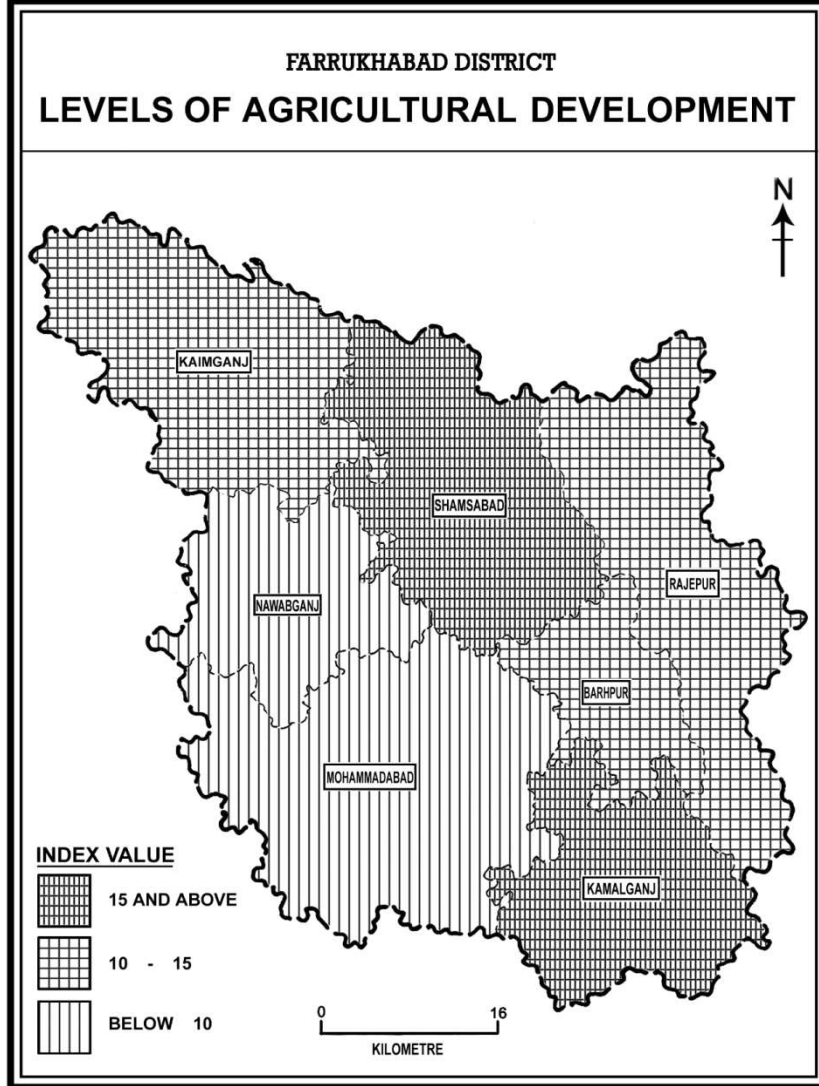


FIG. 2

स्तर पाया जा सकता है। संतुलित नियोजन हेतु कृषि का विकास एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्तर को बढ़ाना अति आवश्यक है। विस्तृत विवरण हेतु सारणी क्रमांक 2 एवं मानचित्र क्रमांक 2 में देखा जा सकता है।

कृषि विकास हेतु नियोजन

ग्रामीण विकास प्रक्रिया में कृषि नियोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष है। ग्रामीण जनसंख्या

कोटि
म
न
व
म
म
न
व

का मुख्य आर्थिक आधार कृषि सम्बन्धित क्रियायें हैं। इसमें संशोधन एवं परिमार्जन करके ही निरन्तर बढ़ रही मांगों की पूर्ति सम्भव है। फर्रुखाबाद जैसे जनपद जिसकी आय का अधिकांश भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है तथा अधिकांश श्रमिक कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं; ग्रामीण कृषि नियोजन समाकलित ग्रामीण विकास की दिशा में एक सामयिक एवं सही प्रयास है। नियोजन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवं संशोधन की सुविधा के साथ समयानुसार परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में परिवर्तन की सम्भावना रहनी चाहिए। कृषि नियोजन का उद्देश्य ग्रामीण समाज को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जो परिवर्तित सामाजिक प्राविधिकीय परिस्थिति के अनुकूल समाज के सदस्यों के लिये सर्वाधिक हित के साधन प्रस्तुत कर सकें।⁶

कृषि नियोजन हेतु प्राकृतिक, आर्थिक, प्राविधिकीय एवं सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित करके कृषि नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है क्योंकि उक्त तत्वों के समन्वित प्रभाव से ही समाकलित ग्रामीण विकास की अवधारणा विकसित होती है। किसी क्षेत्र के कृष्येत्तर रोजगार अवसरों में वृद्धि, विकास कार्यक्रमों की आत्मनिर्भरता, जागरूकता तथा स्थानीय जनसहयोग कृषि नियोजन कार्यक्रम के मुख्य तत्व हैं। कृषि नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य कृषि से सम्बन्धित व्यक्तियों को आंशिक तथा बेरोजगार ग्रामीण जनसंख्या को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान करना है।⁷ राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु निर्यात की जानी वाली फसलों जैसे – तम्बाकू, जूट, कपास, गन्ना, मसाला एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रयास भी कृषि नियोजन का एक अंग है। तीव्र गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या, औद्योगीकरण व अनियोजित नगरीकरण के परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि का तीव्रता से हास हो रहा है। कृषि व मानव हित को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो जाता है कि इसको रोकने के उपाय सोचे जायें।

भारतीय कृषि को समय के साथ चलाने हेतु नवीनतम शोधों और तकनीकों का सहारा लेना होगा। कृषि उत्पादों की पैकेजिंग को और अधिक संशोधित करना होगा। कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, प्रमाणन और विपणन की सम्पूर्ण व्यवस्था को नवीनीकृत करना होगा। कृषि के विकास और वाणिज्यीकरण की दिशा में 'गाँधी आश्रम' एक आधार स्तम्भ है। गाँधी आश्रम उद्योगों, लघु और ग्रामोद्योगों के लिए एक मुख्य विपणन केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित है। गाँधी आश्रम जैसी संस्थाओं को नवीनीकृत करके व्यक्तियों को इससे जोड़ने की आवश्यकता है। अरोड़ा⁸ के शब्दों में "यह विशेष विचारणीय है कि किसी क्षेत्र के विकास में जो प्रणाली या योजना सफल हुई है उसे पूर्ण रूप से दूसरे क्षेत्र में संचालित नहीं किया जा सकता है।"

निष्कर्ष

जिस जनपद की 77.92 प्रतिशत जनसंख्या कृषि की धुरी पर घूमती हो और उस क्षेत्र की ही सबसे अधिक उपेक्षा हो; तो यह उस क्षेत्र का ही नहीं अपितु उस देश का भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कृषि प्रधानता जिस अनुपात में मुहावरे की तरह भाषाई व्यवहार में प्रयुक्त हुई है, उसी अनुपात में क्रियाशील व्यवहार में उपेक्षित रही है। देश एवं जनपद फर्रुखाबाद का कृषि व्यवहार ऐसा ही है जो देश की रीढ़ की हड्डी होने पर भी केन्द्रीय विचार-विमर्श की परिधि में नहीं आता है। कृषि के विकास और विस्तार की नीति से कृषकों के वंचित रहने से ही जमींदारी उन्मूलन,

भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी एवं कम फसल मूल्य की उपलब्धता आदि जैसे अनेक कार्य अब तक राजनीतिक विवशता के रूप में सामने आये हैं। वे लोग जो मात्र कृषि या औद्योगिक उत्पादन के विषय में ही चिन्तित रहते हैं वे देश की सर्वांगीण अर्थव्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। जब दोनों (कृषि और औद्योगिकीकरण) की बात एक साथ होगी तभी आर्थिक गतिविधियों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा और उन्नति के पथ पर निरन्तर अग्रसर होकर कृषि और उद्योगों के साथ न्याय किया जा सकेगा जो अभी तक अपनी वास्तविक लोकतान्त्रिक नियति से वंचित है।

संदर्भ ग्रंथ

- 1 बाजपेयी, ए0डी0एन (1989) ग्रामीण विकास नियोजन में प्राथमिकताओं का निर्धारण : ग्रामीण विकास संकल्पना उपागम एवं मूल्यांकन, कुरुक्षेत्र, जून, पृ0 28.
2. सिंह, अजब, (2010) ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनायें, कुरुक्षेत्र, मार्च, पृ0 21.
3. श्रीवास्तव, दिलीप कुमार, (1992) विकासखण्ड बेरुआरवारी (बलिया) में समन्वित ग्रामीण विकास हेतु योजना, अप्रकाशित षोध प्रबन्ध, पूर्वांचल वि0वि0, जौनपुर, पृ0 69-70.
4. भार्गव, एस0 पी0, (2006) ग्रामीण विकास की दिशा में नई पहल, प्रतियोगिता दर्पण, मई पृ0 1819.
5. उपाध्याय, आर्येन्द्र, (2008) समन्वित ग्रामीण विकास की रूपरेखा, कुरुक्षेत्र, जून, पृ0 17.
6. सिंह, सत्येन्द्र, (1985) समन्वित ग्राम्य विकास : अवधारणा, अभिप्राय एवं उद्देश्य, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, दिसम्बर पृ0 21.
- 7- Tripathi, S.K. (1991) Spatial Organisation and Microlevel Planning of Auraiya Tehsil, District Etawah (U.P.) Unpublished Ph.D. Thesis, p. 293.
- 8- Arora, R.C. (1976) Integrated Rural Development, S.Chand & Company Ltd., New Delhi, pp. 3-4.